city भास्कर

JAIPUR, FRIDAY, 16/03/2018

शहर के चरित्र को विकसित करने से ही बनेगी स्मार्ट सिटी

सिटी रिपोर्टर | भारत में स्मार्ट सिटी को लेकर नई-नई धारणाएं बुनी जा रही हैं। दूसरे देशों की चकाचौंध की नकल करने की बजाय हर शहर को उसकी विरासत और चरित्र को पहचान कर उसी आधार पर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना चाहिए। स्मार्ट सिटी का मतलब ही यही है कि उस शहर में घुसने पर उसकी पहचान की छाप दिखनी चाहिए। यह बात एनजी ग्लोबल एफजेड एलएएलसी के

सीईओ एवं दुबई के स्मार्ट सिटी कंसल्टेंट एन.जी. थॉमस ने गुरुवार को कही। वे एक होटल में चल रही स्मार्ट एंड डिजिटल राजस्थान समिट एंड एक्सपो के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे।

टैक्स वसूलो,, सुविधाएं दो : आईजीबीसी की पॉलिसी एंड एडवोकेसी कमेटी के चेयरमैन वी.सुरेश ने कहा कि स्मार्ट सिटीज को स्मार्ट ग्रीन सिटीज में बदलने की जरूरत है। स्मार्ट सिटीज के लिए बांड्स, ग्रांट्स, टैक्स कलेक्शन आदि के जरिए वित्तीय संसाधन जुटाने में निजी और सरकारी क्षेत्र के मध्य उचित संतुलन आवश्यक है।

जयपुर, शुक्रवार, 16 मार्च 2018
डेली न्यूज़

ANCHOR - event

बिजली की खपत कम होगी, कचरे का बेहतर निस्तारण होगा

'स्मार्ट सिटीज को स्मार्ट ग्रीन सिटीज में बदलने की जरूरत'

दो दिवसीय स्मार्ट एंड डिजीटल राजस्थान समिट एंड एक्सपो का समापन

डेली न्यूज, mix रिपोर्टर

जयपुर। स्मार्ट सिटीज को स्मार्ट ग्रीन सिटीज में बदलने की जरूरत है। इससे पानी, बिजली की खपत कम होगी, कचरे का बेहतर निस्तारण होगा और लोगों को अच्छी आवास सुविधा मिल सकेगी। स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए वित्तीय संसाधन आवश्यक हैं। स्मार्ट सिटीज के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने में निजी और सरकारी क्षेत्र के बीच संतुलन आवश्यक है। ये बात आईजीबीसी की पॉलिसी एंड एडवोकेसी कमेटी के चेयरमैन वी. सुरेश ने कही। वे गुरुवार को होटल जयपुर मैरियट में स्मार्ट एंड डिजीटल राजस्थान समिट एंड एक्सपो 2018 के समापन सत्र में सम्बोधित कर रहे थे। इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से राजस्थान सरकार एवं 'द गिल्ड' के सहयोग से आयोजित समिट का समापन गुरुवार को हुआ। वहीं एनजी ग्लोबल एफजेड एलएलसी के सीईओ एवं दुबई के स्मार्ट सिटी कंसल्टेंट, एन.जी. थॉमस ने कहा कि भारत की स्मार्ट सिटी अवधारणा में अन्य देशों की नकल नहीं होनी चाहिए। भारत की स्मार्ट सिटीज के विकास में योगदान देने वाली सबसे बड़ी ऐसेट इसमें रहने वाले लोग हैं। स्मार्ट सिटीज में पहले दिन से ही पैसा जेनरेट करना चाहिए। सेवाओं को उपलब्ध कराने के बदले छोटा सा शुल्क लें तो सकारात्मक वित्तीय परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।

फर्स्ट सेशन : सफलता की कुंजी है तकनीक, नवाचार और सहयोग

सेंटर फॉर रिसर्च इन अर्बन अफेयर्स इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनोमिक चेंज की प्रो. कला सीतारमन श्रीधर ने कहा कि ई-कॉमर्स और इंटरनेट जैसे नए आर्थिक उद्योग पनपना इस बात का संकेत है कि प्राचीन आर्थिक उद्योग विफल रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि 'वर्क फ्रॉम होम' जैसी अवधारणाओं से ट्रैफिक और प्रदूषण कम होता है। भारत में बचत की दर 31 प्रतिशत है, जबकि अमेरिका में यह सिर्फ 17 प्रतिशत है। यह इसलिए है कि भारत में आज भी लोग भुगतान के लिए नकदी का इस्तेमाल करते हैं। नकद भुगतान से खर्च पर नियंत्रण रहता है। इस दौरान रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट स्मार्ट ग्रिड अजय राजपानी, राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड के डायरेक्टर (टी) उदय शंकर, नेटएप इंडिया के सिस्टम इंजीनियर कृष्ण परमार ने भी विचार रखे।

सैकंड सेशन : थिंकिंग पीपल टुगेदर– रिट्राइविंग फॉर मोर एक्टिव, सेफ, रेजिलियंट एंड एंगेज्ड कम्यूनिटीज

कर्नाटक लोकायुक्त एवं बैंगलुरु के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक संजय सहाय ने कहा कि स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम के लिए शहरों में कैमरे वहीं होने चाहिए, जहां इनकी आवश्यकता हो और इसमें कवरेज एरिया का ध्यान भी रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त ऑपरेशनल सेंटर्स और प्रशिक्षित कांस्टेबल्स के जरिए तकनीक का बेहतर इस्तेमाल भी होना चाहिए। सूरत नगर निगम के उपायुक्त एवं स्मार्ट सिटी सूरत के सीईओ नागराजन एम. ने कहा कि भारत में स्मार्ट सिटीज के विकास में एक बड़ी चुनौती राज्य व केन्द्र के मध्य संवाद और समन्वय की कमी है।

दैनिक नवज्योति
जयपुर
शुक्रवार, 16 मार्च 2018

राजस्थान में लगेंगे 2.50 लाख स्मार्ट मीटर

स्मार्ट एंड डिजीटल राजस्थान समिट एंड एक्सपो में हुआ मंथन

शहरों में कैमरे वहीं होने चाहिए, जहां इनकी आवश्यकता हो

नवज्योति एक्सप्रेस

भारत की स्मार्ट सिटी अवधारणा में अन्य देशों की नकल नहीं होनी चाहिए। इसमें भारत का अनूठा व्यक्तित्व और स्टाइल दिखना चाहिए। यह बात एनजी ग्लोबल एफजेड एलएएलसी के सीईओ एवं दुबई के स्मार्ट सिटी कंसल्टेंट, एन.जी. थॉमस ने कही।

वे गुरूवार को होटल जयपुर मैरियट में स्मार्ट एंड डिजीटल राजस्थान समिट एंड एक्सपो 2018 के समापन सत्र में सम्बोधित कर रहे थे। भारत की स्मार्ट सिटीज के विकास में योगदान देने वाली सबसे बड़ी ऐसेट इसमें रहने वाले लोग है। स्मार्ट सिटीज में पहले दिन से ही पैसा जेनरेट करना चाहिए। विभिन्न सेवाओं को उपलब्ध कराने के बदले बड़ी जनसंख्या से छोटा या शुल्क लिया जाए तो सकारात्मक वित्तीय परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इस अवसर पर आईजीबीसी की पॉलिसी एंड एडवोकेसी कमेटी के चेयरमैन, वी. सुरेश ने कहा कि स्मार्ट सिटीज को स्मार्ट ग्रीन सिटीज में बदलने की जरूरत है। इससे इन शहरों में पानी, बिजली की खपत कम होगी, कचरे का बेहतर विस्तारण होगा और इनमें रहने वालों को अच्छी आवास सुविधा मिल सकेगी। इस अवसर पर जे.मोहनको कंस्ट्रक्शन के मैनेजिंग पार्टनर जैमिनी उबेरॉय ने कहा कि कई कम्पनियां भी स्मार्ट, डिजीटल और ग्रीन होने के लिए प्रतिबद्ध है। एआईसीसी की रीजनल चाइस प्रेसीडेंट अरूणा सेठी ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

पहला सत्र

स्मार्ट सिटी की सफलता की कुंजी है तकनीक, नवाचार और सहयोग

सेंटर फॉर रिसर्च इन अर्बन अफेयर्स इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनोमिक चेंज की प्रोफेसर, डॉ. कला सीतारमन श्रीधर ने कहा कि ई-कॉमर्स और इंटरनेट जैसे नए आर्थिक उद्योग पनपना इस बात का संकेत है कि प्राचीन आर्थिक उद्योग विफल रहे हैं। ई-कॉमर्स में अमेजन, जबोंग आदि के जरिए ऑन लाइन शॉपिंग ने शॉपिंग के परम्परागत तरीके बदल दिए हैं। भारत में बचत की दर 31 प्रतिशत है, जबकि अमेरिका में यह सिर्फ 17 प्रतिशत है। सीनियर वाइस प्रेसीडेंट स्मार्ट गिड, रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर अजय राजपाली ने कहा कि वर्तमान में खुशहाल समुदाय बनाने की आवश्यकता है जो उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर्स जैसी सुविधाएं दे। राजस्थान में 2.50 लाख स्मार्ट मीटर लगाया जाना प्रस्तावित है। डायरेक्टर (टी) राजकॉम्प इनफो सर्विसेज लिमिटेड के उदय शंकर ने कहा कि ऐसा इन्फ्रास्ट्रक्चर जो अच्छे नेटवर्क और बेहतर कनेक्टिविटी में सक्षम हो, गांवों तक पहुंचना चाहिए। राजस्थान सरकार के नवाचार जैसे ई-मित्र प्लस, इलेक्ट्रोनिक हैल्थ रिकार्ड (ईएचआर), सर्विलांस के लिए ड्रोन्स और मोबाइल वैन्स आदि से लोगों को स्मार्ट और डिजीटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। नेटएप इंडिया के सिस्टम इंजीनियर कृष्ण परमार ने 'इनोवेटिंग टू हैल्प वेंज द वर्ल्ड विद डाटा' विषय पर प्रजेंटेशन दिया। इस प्रजेंटेशन में नागरिकों के लिए डाटा के ऐसे विकल्प उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।

दूसरा सत्र

ब्रिगिंग पीपल टुगेदर- स्ट्राइविंग फॉर मोर एक्टिव, सेफ, रेजिलियंट एंड एंगेज्ड कम्युनिटीज

कर्नाटक लोकायुक्त एवं बंगलौर के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक संजय सहाय ने कहा कि स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम के लिए शहरों में कैमरे वहीं होने चाहिए, जहां इनकी आवश्यकता हो और इसमें कवरेज एरिया का ध्यान भी रखना चाहिए। इसके ऑपरेशनल सेंटर्स और प्रशिक्षित कांस्टेबल्स के जरिए तकनीक का बेहतर इस्तेमाल भी होना चाहिए। इस मामले में मॉनिटरिंग और प्रगति का आकलन अभी भी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। नियमित ऑडिट और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के परीक्षणों से इस मुद्दे का समाधान किया जा सकता है। सूरत नगर निगम के उपायुक्त एवं स्मार्ट सिटी सूरत के सीईओ नागराजन एम. ने कहा कि भारत में स्मार्ट सिटीज के विकास में एक बड़ी चुनौती राज्य व केन्द्र के मध्य संवाद और समन्वय की कमी है। राजस्थान सोलर एसोसिएशन के महासचिव सुनील बंसल ने कहा कि ग्रीन एनर्जी की लागत ज्यादा होने के बावजूद सरकार को इस पर ध्यान देना होगा ताकि शहरों को लोगों के रहने लायक बनाया जाए और नागरिक खुश रहें। स्ट्रीटलाइट्स, सेंसर लाइट्स, गार्डन लाइट्स के लिए सरकार को नीतियां बनानी चाहिए। वाइब्रेंट सोलर के एमडी आर.एस. राजपुरोहित ने भी इस अवसर पर अपने विचार साझा किए।

पंजाब केसरी
JAIPUR
16 मार्च, 2018, शुक्रवार

स्मार्ट सिटीज को स्मार्ट ग्रीन सिटी में बदलने की जरूरत

चर्चा

- स्मार्ट एंड डिजीटल राजस्थान समिट एंड एक्सपो 2018 का समापन

पंजाब केसरी/जयपुर

आज देश में स्मार्ट सिटीज बनाने पर जो काम चल रहा है, उसमें ग्रीन सिटीज बनाने पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इससे न केवल इन शहरों में पानी, बिजली की खपत कम होगी, कचरे का बेहतर निस्तारण होगा। ये बात गुरुवार को स्मार्ट एंड डिजीटल राजस्थान समिट एंड एक्सपो 2018 के समापन सत्र को सम्बोधित करते हुए आईजीबीसी की पॉलिसी एंड एडवोकेसी कमेटी के चेयरमैन वी. सुरेश ने कही। वहीं दूसरी तरफ दुबई के स्मार्ट सिटी कंसल्टेंट एन.जी. थॉमस ने कहा कि भारत की स्मार्ट सिटी अवधारणा में अन्य देशों की नकल नहीं होनी चाहिए। इसमें भारत का अनूठा व्यक्तित्व और स्टाइल दिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की स्मार्ट सिटीज के विकास में योगदान देने वाली सबसे बड़ी ऐसेट इसमें रहने वाले लोग हैं।

स्मार्ट एंड डिजीटल राजस्थान समिट एंड एक्सपो 2018 के समापन सत्र में मंचासीन अतिथि।

लगेंगे स्मार्ट मीटर: एक्सपो को संबोधित करते हुए रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के सीनियर वाइस प्रेसीडेंट अजय राजपानी ने कहा कि वर्तमान में खुशहाल समुदाय बनाने की आवश्यकता है, जो उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर्स जैसी सुविधाएं दे। राजस्थान में 2.50 लाख स्मार्ट मीटर लगाया जाना प्रस्तावित है। इससे उपभोक्ताओं को स्वयं की बिजली की खपत पर नजर रखने में सहायता मिलेगी और वे बिजली की खपत पर नियंत्रण कर अपनी लागत कम कर सकेंगे।

समाचार जगत

जयपुर, 16 मार्च 2018

'भारत की स्मार्ट सिटी अवधारणा में दिखना चाहिए इसका अनूठा व्यक्तित्व और स्टाइल : एनजी थॉमस

स्मार्ट एंड डिजीटल राजस्थान समिट एंड एक्सपो-2018 का समापन

जयपुर (कासं)। भारत की स्मार्ट सिटी अवधारणा में अन्य देशों की नकल नहीं होनी चाहिए। इसमें भारत का अनूठा व्यक्तित्व और स्टाइल दिखना चाहिए। यह बात एनजी ग्लोबल एफजेड एलएएलसी के सीईओ एवं दुबई के स्मार्ट सिटी कंसल्टेंट, एन.जी. थॉमस ने कही। वे गुरुवार को होटल जयपुर मेरियट में स्मार्ट एंड डिजीटल राजस्थान समिट एंड एक्सपो 2018 के समापन सत्र में सम्बोधित कर रहे थे। भारत की स्मार्ट सिटीज के विकास में योगदान देने वाली सबसे बड़ी ऐसेट में रहने वाले लोग हैं। स्मार्ट सिटीज में पहले दिन से ही पैसा जेनरेट करना चाहिए। विभिन्न सेवाओं को उपलब्ध कराने के बदले बड़ी जनसंख्या से छोटा सा शुल्क लिया जाएं तो सकारात्मक वित्तीय परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इस अवसर पर आईजीबीसी की पॉलिसी एंड एडवोकेसी कमेटी के चेयरमैन, वी. सुरेश ने कहा कि स्मार्ट सिटीज को स्मार्ट ग्रीन सिटीज में बदलने की जरूरत है। इससे इन शहरों में पानी, बिजली की खपत कम होगी, कचरे का बेहतर निस्तारण होगा और इनमें रहने वालों को अच्छी आवास सुविधा मिल सकेगी। इस अवसर पर जे.मोहनको. कंस्ट्रक्शन्स के मैनेजिंग पार्टनर, जैमिनी उबेरॉय ने कहा कि कई कम्पनियां भी स्मार्ट, डिजिटल और ग्रीन होने के लिए प्रतिबद्ध है। एआईसीसी की रीजनल वाइस प्रेसीडेंट, अरूणा सेठी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। पहले सत्र के दौरान सेंटर फॉर रिसर्च इन अर्बन अफेयर्स इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनोमिक चेंज की प्रोफेसर, डॉ. कला सीतारमन श्रीधर ने कहा कि ई-कॉमर्स और इंटरनेट जैसे नए आर्थिक उद्योग पनपना इस का बात का संकेत है कि प्राचीन आर्थिक उद्योग विफल रहे हैं।

कर्नाटक लोकायुक्त एवं बंगलौर के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक संजय सहाय ने कहा कि स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम के लिए शहरों में कैमरे वहीं होने चाहिए जहां इनकी आवश्यकता हो और इसमें कवरेज एरिया का ध्यान भी रखना चाहिए। राजस्थान सोलर एसोसिएशन के महासचिव, सुनील बंसल ने कहा कि ग्रीन एनर्जी की लागत ज्यादा होने के बावजूद सरकार को इस पर ध्यान देना होगा ताकि शहरों को लोगों के रहने लायक बनाया जाए और नागरिक खुश रहें।

स्ट्रीटलाइट्स, सेंसर लाइट्स, गार्डन लाइट्स के लिए सरकार को नीतियां बनानी चाहिए। वाइब्रेंट सोलर के एमडी आर.एस. राजपुरोहित ने भी इस अवसर पर अपने विचार साझा किये।

दैनिक जलतेदीप

जयपुर, शुक्रवार 16 मार्च 2018

भारत की स्मार्ट सिटी अवधारणा में दिखना चाहिए अनूठा व्यक्तित्व और स्टाइल : एन.जी. थॉमस

■ जलतेदीप कासं, जयपुर

भारत की स्मार्ट सिटी अवधारणा में अन्य देशों की नकल नहीं होनी चाहिए। इसमें भारत का अनूठा व्यक्तित्व और स्टाइल दिखनी चाहिए। यह बात एनजी ग्लोबल एफजेड एलएएलसी के सीईओ एवं दुबई के स्मार्ट सिटी कंसल्टेंट एन.जी. थॉमस ने कही। वे गुरुवार को होटल जयपुर मेरियट में स्मार्ट एंड डिजिटल राजस्थान समिट एंड एक्सपो-2018 के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत की स्मार्ट सिटीज के विकास में योगदान देने वाली सबसे बड़ी संपत्ति इसमें रहने वाले लोग हैं। स्मार्ट सिटीज में पहले दिन से ही पैसा जेनरेट करना चाहिए। विभिन्न सेवाओं को उपलब्ध कराने के बदले बड़ी जनसंख्या से छोटा सा शुल्क लिया जाए तो सकारात्मक वित्तीय परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।

इस अवसर पर आईजीबीसी की पॉलिसी एंड एडवोकेसी कमेटी के चेयरमैन वी. सुरेश ने कहा कि स्मार्ट सिटीज को स्मार्ट ग्रीन सिटीज में बदलने की जरूरत है। इससे इन शहरों में पानी-बिजली की खपत कम होगी, कचरे का बेहतर निस्तारण होगा और इनमें रहने वालों को अच्छी आवास सुविधा मिल सकेगी। स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए वित्तीय संसाधन आवश्यक हैं। स्मार्ट सिटीज के लिए बांड्स, ग्रांट्स, टैक्स कलेक्शन आदि के जरिए वित्तीय संसाधन जुटाने में निजी और सरकारी क्षेत्र के मध्य उचित संतुलन आवश्यक है।

इस अवसर पर जे.मोहनको कंस्ट्रक्शंस के मैनेजिंग पार्टनर जैमिनी उबेरॉय ने कहा कि कई कंपनियां भी स्मार्ट, डिजिटल और ग्रीन होने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एआईसीसी की रीजनल वाइस प्रेसीडेंट अरुणा सेठी ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

पहला सत्र - स्मार्ट सिटी की सफलता की कुंजी है तकनीक, नवाचार और सहयोग

सेंटर फॉर रिसर्च इन अर्बन अफेयर्स इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज की प्रोफेसर डॉ. कला सीतारमण श्रीधर ने कहा कि ई-कॉमर्स और इंटरनेट जैसे नए आर्थिक उद्योग पनपना इस का बात के संकेत हैं कि प्राचीन आर्थिक उद्योग विफल रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि 'वर्क फ्रॉम होम' जैसी अवधारणाओं से ट्रैफिक और प्रदूषण कम होता है। इसी तरह ई-कॉमर्स में अमेजन, जबोंग आदि के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग ने शॉपिंग के परंपरागत तरीके बदल दिए हैं। भारत में बचत की दर 31 प्रतिशत है, जबकि अमेरिका में यह सिर्फ 17 प्रतिशत है। यह इसलिए है कि भारत में आज भी लोग भुगतान के लिए नकदी का इस्तेमाल करते हैं। नकद भुगतान से खर्च पर नियंत्रण रहता है।

दैनिक
कंचन केसरी

जयपुर, शुक्रवार 16 मार्च 2018

स्मार्ट एंड डिजीटल राजस्थान समिट एंड एक्सपो 2018 का हुआ समापन

स्मार्ट सिटी अवधारणा में दिखना चाहिए भारतीय स्टाइलः थॉमस

भारत की स्मार्ट सिटी अवधारणा में अन्य देशों की नकल नहीं होनी चाहिए। इसमें भारत का अनूठा व्यक्तित्व और स्टाइल दिखना चाहिए। यह बात एनजी ग्लोबल एफजेड एलएएलसी के सीईओ एवं दुबई के स्मार्ट सिटी कंसल्टेंट, एन.जी. थॉमस ने कही।

कंचन केसरी

जयपुर/कासं। एनजी ग्लोबल एफजेड एलएएलसी के सीईओ एवं दुबई के स्मार्ट सिटी कंसल्टेंट, एन.जी. थॉमस ने स्मार्ट एंड डिजीटल राजस्थान समिट एंड एक्सपो 2018 के समापन सत्र को सम्बोधित करते हुए कहा कि भारत की स्मार्ट सिटीज के विकास में योगदान देने वाली सबसे बड़ी ऐसेट इसमें रहने वाले लोग हैं। स्मार्ट सिटीज में पहले दिन से ही पैसा जेनरेट करना चाहिए। विभिन्न सेवाओं को उपलब्ध कराने के बदले बड़ी जनसंख्या से छोटा सा शुल्क लिया जाए तो सकारात्मक वित्तीय परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।

स्मार्ट सिटीज को स्मार्ट ग्रीन सिटीज में बदलने की जरूरत

आईजीबीसी की पॉलिसी एंड एडवोकेसी कमेटी के चेयरमैन, वी. सुरेश ने कहा कि स्मार्ट सिटीज को स्मार्ट ग्रीन सिटीज में बदलने की जरूरत है। इससे इन शहरों में पानी, बिजली की खपत कम होगी, कचरे का बेहतर निस्तारण होगा और इनमें रहने वालों को अच्छी आवास सुविधा मिल सकेगी। स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए वित्तीय संसाधन आवश्यक हैं। स्मार्ट सिटीज के लिए बांड्स, ग्रांट्स, टैक्स कलेक्शन, आदि के जरिए वित्तीय संसाधन जुटाने में निजी और सरकारी क्षेत्र के मध्य उचित संतुलन आवश्यक है। इस अवसर पर जे. मोहन को कंस्ट्रक्शन्स के मैनेजिंग पार्टनर, जैमिनी उबेरॉय ने कहा कि कई कम्पनियां भी स्मार्ट, डिजीटल और ग्रीन होने के लिए प्रतिबद्ध है। एआईसीसी की रीजनल वाइस प्रेसीडेंट, अरूणा सेठी ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

भारत में बचत की दर 31 प्रतिशत

सेंटर फॉर रिसर्च इन अर्बन अफेयर्स इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनोमिक चेंज की प्रोफेसर, डॉ. कला सीतारमन श्रीधर ने कहा कि ई-कॉमर्स और इंटरनेट जैसे नए आर्थिक उद्योग पनपना इस का बात का संकेत है कि प्राचीन आर्थिक उद्योग विफल रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि वर्क फ्रॉम होम जैसी अवधारणाओं से ट्रैफिक और प्रदूषण कम होता है। इसी तरह ई-कॉमर्स में अमेजन, जबोंग आदि के जरिए ऑन लाइन शॉपिंग ने शॉपिंग के परम्परागत तरीके बदल दिए है। भारत में बचत की दर 31 प्रतिशत है, जबकि अमेरिका में यह सिर्फ 17 प्रतिशत है। यह इसलिए है कि भारत में आज भी लोग भुगतान के लिए नकदी का इस्तेमाल करते हैं। नकद भुगतान से खर्च पर नियंत्रण रहता है।

राज वैभव जयपुर, शुक्रवार, 16 मार्च, 2018

"भारत की स्मार्ट सिटी अवधारणा में दिखना चाहिए इसका अनूठा व्यक्तित्व और स्टाइल"

जयपुर। भारत की स्मार्ट सिटी अवधारणा में अन्य देशों की नकल नहीं होनी चाहिए। इसमें भारत का अनूठा व्यक्तित्व और स्टाइल दिखना चाहिए। यह बात एनजी ग्लोबल एफजेड एंलएएलसी के सीईओ एवं दुबई के स्मार्ट सिटी कंसल्टेंट, एन.जी. थॉमस ने कही। वे आज होटल जयपुर मेरियट में स्मार्ट एंड डिजीटल राजस्थान समिट एंड एक्सपो 2018 के समापन सत्र में सम्बोधित कर रहे थे। भारत की स्मार्ट सिटीज के विकास में योगदान देने वाली सबसे बड़ी ऐसेट इसमें रहने वाले लोग है। स्मार्ट सिटीज में पहले दिन से ही पैसा जेनरेट करना चाहिए। विभिन्न सेवाओं को उपलब्ध कराने के बदले बड़ी जनसंख्या से छोटा सा शुल्क लिया जाएं तो सकारात्मक वित्तीय परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।

इस अवसर पर आईजीबीसी की पॉलिसी एंड एडवोकेसी कमेटी के चेयरमैन, वी. सुरेश ने कहा कि स्मार्ट सिटीज को स्मार्ट ग्रीन सिटीज में बदलने की जरुरत है। इससे इन शहरों में पानी, बिजली की खपत कम होगी, कचरे का बेहतर निस्तारण होगा और इनमें रहने वालों को अच्छी आवास सुविधा मिल सकेगी। स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए वित्तीय संसाधन आवश्यक हैं। स्मार्ट सिटीज के लिए बांड्स, ग्रांट्स, टैक्स कलेक्शन, आदि के जरिए वित्तीय संसाधन जुटाने में निजी और सरकारी क्षेत्र के मध्य उचित संतुलन आवश्यक है।

इस अवसर पर जे. मोहन को कंस्ट्रक्शन्स के मैनेजिंग पार्टनर, जैमिनी उबेरॉय ने कहा कि कई कम्पनियां भी स्मार्ट, डिजीटल और ग्रीन होने के लिए प्रतिबद्ध है। एआईसीसी की रीजनल वाइस प्रेसीडेंट, सुश्री अरूणा सेठी ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

पहला सत्र- स्मार्ट सिटी की सफलता की कुंजी है तकनीक, नवाचार और सहयोग: सेंटर फॉर रिसर्च इन अर्बन अफेयर्स इंस्टीट्यूट ऑफ सोश्यल एंड इकोनोमिक चेंज की प्रोफेसर, डॉ. कला सीतारमन श्रीधर ने कहा कि ई-कॉमर्स और इंटरनेट जैसे नए आर्थिक उद्योग पनपना इस का बात का संकेत हैं कि प्राचीन आर्थिक उद्योग विफल रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि 'वर्क फ्रॉम होम' जैसी अवधारणाओं से ट्रेफिक और प्रदूषण कम होता है। इसी तरह ई-कॉमर्स में अमेजन, जबोंग आदि के जरिए ऑन लाइन शॉपिंग ने शॉपिंग के परम्परागत तरीके बदल दिये हैं। भारत में बचत की दर 31 प्रतिशत है, जबकि अमेरिका में यह सिर्फ 17 प्रतिशत है। यह इसलिए है कि भारत में आज भी लोग भुगतान के लिए नकदी का इस्तेमाल करते है। नकद भुगतान से खर्च पर नियंत्रण रहता है।

सीनियर वाइस प्रेसीडेंट स्मार्ट ग्रिड, रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर, अजय राजपानी ने कहा कि वर्तमान में खुशहाल समुदाय बनाने की आवश्यकता है जो उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर्स जैसी सुविधाएं दे। राजस्थान में 2.50 लाख स्मार्ट मीटर लगाया जाना प्रस्तावित है। इससे उपभोक्ताओं को स्वयं की बिजली की खपत पर नजर रखने में सहायता मिलेगी और वे बिजली की खपत पर नियंत्रण कर अपनी लागत कम कर सकेंगे।

डायरेक्टर (टी) राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड के उदय शंकर ने कहा कि ऐसा इन्फ्रास्ट्रक्चर जो अच्छे नेटवर्क और बेहतर कनेक्टिविटी में सक्षम हो, गांवों तक पहुंचना चाहिए। छोटे शुल्क के बदले नागरिकों को सिंगल प्लेटफार्म पर सरकारी सुविधाएं मिल जाएं तो यह उनके लिए काफी लाभदायक है। राजस्थान सरकार के नवाचार जैसे ई-मित्र प्लस, इलेक्ट्रोनिक हैल्थ रिकार्ड (ईएचआर), सर्विलांस के लिए ड्रोन्स और मोबाइल वैन्स आदि से लोगों को स्मार्ट और डिजीटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी।

नेटएप इंडिया के सिस्टम इंजीनियर, कृष्ण परमार ने 'इनोवेटिंग टू हैल्प चेंज द वर्ल्ड विद डाटा' विषय पर प्रजेंटेशन दिया। इस प्रजेंटेशन में नागरिकों के लिए डाटा के ऐसे विकल्प उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया जो सुरक्षित, कुशल और भविष्य में भी उपयोगी हो।

द्वितीय पैनल सत्र-ब्रिगिंग पीपल टुगेदर-स्ट्राइविंग फॉर मोर एक्टिव, सेफ, रेजिलियंट एंड एंगेज्ड कम्युनिटीज: कर्नाटक लोकायुक्त एवं बंगलौर के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, संजय सहाय ने कहा कि स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम के लिए शहरों में कैमरे वहीं होने चाहिए जहां इनकी आवश्यकता हो और इसमें कवरेज एरिया का ध्यान भी रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त ऑपरेशनल सेंटर्स और प्रशिक्षित कॉन्स्टेबल्स के जरिए तकनीक का बेहतर इस्तेमाल भी होना चाहिए। इस मामले में मॉनिटरिंग और प्रगति का आंकलन अभी भी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। नियमित ऑडिट और ट्रेफिक मैनेजमेंट सिस्टम के परीक्षणों से इस मुद्दे का समाधान किया जा सकता है।

सूरत नगर निगम के उपायुक्त एवं स्मार्ट सिटी सूरत के सीईओ, नागराजन एम. ने कहा कि भारत में स्मार्ट सिटीज के विकास में एक बडी चुनौती राज्य व केन्द्र के मध्य संवाद और समन्वय की कमी है।

राजस्थान सोलर एसोसिएशन के महासचिव, सुनील बंसल ने कहा कि ग्रीन एनर्जी की लागत ज्यादा होने के बावजूद सरकार को इस पर ध्यान देना होगा ताकि शहरों को लोगों के रहने लायक बनाया जाए और नागरिक खुश रहें।

स्ट्रीटलाइट्स, सेंसर लाइट्स, गार्डन लाइट्स के लिए सरकार को नीतियां बनानी चाहिए।' वाइब्रेंट सोलर के एमडी आर.एस. राजपुरोहित ने भी इस अवसर पर अपने विचार साझा किये।

राज वैभव जयपुर, शुक्रवार 16 मार्च, 2018

भारत की स्मार्ट सिटी अवधारणा में दिखना चाहिए अनूठा व्यक्तित्व और स्टाइल : एन.जी. थॉमस

जयपुर। भारत की स्मार्ट सिटी अवधारणा में अन्य देशों की नकल नहीं होनी चाहिए। इसमें भारत का अनूठा व्यक्तित्व और स्टाइल दिखनी चाहिए। यह बात एनजी ग्लोबल एफजेड एलएएलसी के सीईओ एवं दुबई के स्मार्ट सिटी कंसल्टेंट एन.जी. थॉमस ने कही। वे गुरुवार को होटल जयपुर मेरियट में स्मार्ट एंड डिजिटल राजस्थान समिट एंड एक्सपो-2018 के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत की स्मार्ट सिटीज के विकास में योगदान देने वाली सबसे बड़ी संपत्ति इसमें रहने वाले लोग हैं। स्मार्ट सिटीज में पहले दिन से ही पैसा जेनरेट करना चाहिए। विभिन्न सेवाओं को उपलब्ध कराने के बदले बड़ी जनसंख्या से छोटा सा शुल्क लिया जाए तो सकारात्मक वित्तीय परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।

इस अवसर पर आईजीबीसी की पॉलिसी एंड एडवोकेसी कमेटी के चेयरमैन वी. सुरेश ने कहा कि स्मार्ट सिटीज को स्मार्ट ग्रीन सिटीज में बदलने की जरूरत है। इससे इन शहरों में पानी-बिजली की खपत कम होगी, कचरे का बेहतर निस्तारण होगा और इनमें रहने वालों को अच्छी आवास सुविधा मिल सकेगी। स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए वित्तीय संसाधन आवश्यक हैं। स्मार्ट सिटीज के लिए बांड्स, ग्रांट्स, टैक्स कलेक्शन आदि के जरिए वित्तीय संसाधन जुटाने में निजी और सरकारी क्षेत्र के मध्य उचित संतुलन आवश्यक है। इस अवसर पर जे.मोहनको कंस्ट्रक्शंस के मैनेजिंग पार्टनर जैमिनी उबेरॉय ने कहा कि कई कंपिनयां भी स्मार्ट, डिजिटल और ग्रीन होने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एआईसीसी की रीजनल वाइस प्रेसीडेंट अरुणा सेठी ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

बुलेटिन टुडे

गुरुवार
15.03.2018

हमारी भौगोलिक स्थितियां अन्य देशों से भिन्न : लाहोटी

जयपुर। जयपुर नगर निगम के महापौर अशोक लाहोटी ने कहा कि स्मार्ट सोल्यूशन्स को लागू करने से पूर्व हमें सीवरेज, प्रदूषण नियंत्रण, इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट, परिवहन के वैकल्पिक साधन और अन्य मूल घटकों के विकास पर ध्यान देना होगा। स्मार्ट एंड डिजिटल राजस्थान समिट और एक्सपो 2018 को संबोधित करते उन्होंने कहा कि विदेशों की तरह स्मार्ट सिटी डवलपमेंट की अवधारणा को यहां ज्यों का त्यों लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे देश की भौगोलिक, डेमोग्राफिक एवं आर्थिक स्थितियां अन्य देशों से भिन्न हैं।

राजस्थान स्टेटमेन्ट

जयपुर गुरूवार, 15 मार्च , 2018

स्मार्ट सिटी से पहले मूलभूत सुविधाओं का विकास होना जरूरी–मेयर

(राजस्थान स्टेटमेन्ट)

जयपुर। स्मार्ट सॉल्यूशन्स को लागू करने से पूर्व हमें सीवरेज, प्रदूषण नियंत्रण, इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट, परिवहन के वैकल्पिक साधन और अन्य मूल घटकों के विकास पर ध्यान देना होगा।

यह बात जयपुर के मेयर, अशोक लाहोटी ने कही है। वे आज जयपुर मैरियट में 'स्मार्ट एंड डिजीटल राजस्थान समिट और एक्सपो 2018' के उद्घाटन सत्र में सम्बोधित कर रहे थे। दो दिवसीय इस समिट का आयोजन इंडो–अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स (आईएसीसी) द्वारा राजस्थान सरकार एवं 'द गिल्ड' के सहयोग से किया जा रहा है। इस आयोजन को राजस्थान सरकार के शहरी विकास एवं आवासन (यूडीएच) विभाग का भी सहयोग प्राप्त है। इस अवसर पर आईएसीसी के एक्जीक्यूटिव वाइस प्रेसीडेंट, डॉ. ललित भसीन ने स्वागत भाषण में बताया कि किसी भी शहर के विकास के स्तर, बदलाव की इच्छा, नागरिकों की महत्वाकांक्षा से उस षहर की स्मार्ट सिटी की परिभाषा तय होती है। स्मार्ट सिटी में ऐसे स्थान आवष्यक है जहां लोग पैदल चल सकें, खुली जगह हो, परिवहन के अच्छे विकल्प उपलब्ध हों और नागरिकों के अनुकूल एवं किफायती प्रशासन हो। इस अवसर पर अमेरिका के अनुभव साझा करते हुए यूएस कमर्शियल सर्विसेज की काउंसलर, ऐलीन क्रोव नेंडी ने कहा कि भारत के स्मार्ट बनने की असीम सम्भावनाएं है।

सांध्य ज्योति दर्पण

जयपुर, गुरुवार, 15 मार्च, 2018

स्मार्ट सिटी के लिए जनता को दें बेहतर सुविधाएं : लाहोटी

सांध्य ज्योति संवाददाता

जयपुर, 15 मार्च। किसी भी शहर को स्मार्ट सिटी बनाने उसमें स्मार्ट सॉल्यूशन्स को लागू करने से पहले वहां की जनता को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना सबसे जरूरी है। जब तक उस शहर में सीवरेज, पानी-बिजली, प्रदूषण नियंत्रण, इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट, परिवहन के वैकल्पिक साधन नहीं होंगे, तब तक स्मार्ट सॉल्यूशन्स को लागू करने का कोई औचित्य नहीं है। ये बात बुधवार को मेयर अशोक लाहोटी ने एक होटल में आयोजित स्मार्ट एंड डिजीटल राजस्थान समिट और एक्सपो 2018 के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करते हुए कही।

दो दिवसीय इस समिट का आयोजन इंडो-अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स (आईएसीसी) द्वारा राजस्थान सरकार और द गिल्ड के सहयोग से किया जा रहा है। इस आयोजन को राजस्थान सरकार के शहरी विकास एवं आवासन (यूडीएच) विभाग का भी सहयोग प्राप्त है। इस अवसर पर आईएसीसी के एक्जीक्यूटिव वाइस प्रेसीडेंट, डॉ. ललित भसीन ने बताया कि किसी भी शहर के विकास के स्तर, बदलाव की इच्छा, नागरिकों की महत्वाकांक्षा से उस शहर की स्मार्ट सिटी की परिभाषा तय होती है। स्मार्ट सिटी में ऐसे स्थान आवश्यक है जहां लोग पैदल चल सकें, खुली जगह हो, परिवहन के अच्छे विकल्प उपलब्ध हों और नागरिकों के अनुकूल एवं किफायती प्रशासन हो। इस मौके पर अमेरिका के अनुभव साझा करते हुए यूएस कमर्शियल सर्विसेज की कमर्शियल काउंसलर, ऐलीन क्रोव नेंडी ने कहा कि भारत के स्मार्ट देश बनने की असीम सम्भावनाएं है। यहां शहरीकरण लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में स्वच्छ जल, बिजली और परिवहन बेहद जरूरी है। अनेक अमेरिकी कम्पनियां स्मार्ट सिटी डवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए स्मार्ट और नए तरह के सॉल्युशन्स उपलब्ध कराती हैं।